मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 24 | जून 1990 | 50 पैसे

एक कैन्टीन मजदूर की कहानी

काम की तलाश में खान 1979 में फरीदाबाद आया । एक फैक्ट्री की कैन्टीन में 90 रुपये महीना वेतन और खाने के बदले 12 घन्टे ड्यूटी से उसने सफर शुरू किया । अब तक वह अमरीकन यूनिवर्सल-गेडोर-ईस्ट इन्डिया पावरलूम-प्रताप स्टील-थॉमसन प्रेस-एस्कार्ट रिसर्च सेन्टर-एस्कार्ट फस्ट प्लांट-गुडइयर-जोनिन्द्रा स्टील-कल्वीनेटर-बीको इन्जीनियरिंग-कटलर हैमर की कैन्टीनों में काम कर चुका है । हर जगह उसे कैन्टीन को ठेकेदार चलाते मिले हैं । कहीं पर भी उसे सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया है । हर जगह उससे 12-14-16 घन्टे रोज की ड्यूटी ली गई है । ईस्ट इण्डिया झगड़े के समय तो खान से लगातार 36-36 घन्टे काम करवाया गया पर कोई ओवर टाइम नहीं दिया गया ।

कुछ फैक्ट्रियों में उसे कैन्टीन के भी "परमानेन्ट" वर्कर मिले जिन्हें ठेकेदार 8 घन्टे ड्यूटी के बदले सरकारी न्यूनतम वेतन देते थे पर खान अब तक कैन्टीन "कैजुअल" वर्कर ही रहा है । जब तब उसकी छुट्टी कर दी जाती है ताकि एक जगह ज्यादा दिन रह कर वह कुछ लफड़ा न कर दे । फैक्ट्रियों में भी खान को कैजुअल वर्कर का ही काम मिला है । बीच-बीच वाली बेरोजगारी के समय उसने जो भी काम मिला वह किया है । तंग हो कर घर भी चला गया था पर फिर फरीदाबाद लौटना पड़ा । भट्टी पर तपने के बाद झुग्गी में पैर फैलाना ही खान की जिन्दगी बन गई है ।

जहाँ भी उसने काम किया है ठेकेदारों को खान पान में मिलावट करते और घटिया सामान इस्तेमाल करते देखा है । खान ने सब जगह यूनियन लीडरों को कैन्टीन में मुफ्त बढ़िया खाना खाते पाया है——ठेकेदार से दारू के पैसे और सिगरेट पैकेट लेते लीडर उसने जगह-जगह देखे हैं । मैनेजमेंट के कैन्टीन इन्चार्ज को ठेकेदारों से मन्थली लेते खान ने देखा है और घटिया सामान के लिये फैक्ट्री मजदूरों की गालियां अन्य कैन्टीन वर्करों के साथ उसने भी खाई हैं——कभी कभार ठेकेदार की धुनाई होते भी देखी है ।

ज्यादा समय काम और कम वेतन के साथ-साथ ठेकेदार बात-बात पर कैन्टीन वर्करों का अपमान करते हैं । गुडइयर-प्रताप स्टील-पावरलूम-कटलर हैमर में खान ने इस सबका विरोध किया तो उसे गेट बाहर कर दिया गया । जैसा ढर्रा चल रहा है यहीं चलता रहा तो जिन्दगी में खान को कुछ भी नजर नहीं आता । वह संघर्ष में विश्वास करता है पर अकेले तो संघर्ष हो नहीं सकता और कैन्टीन के कैजुअल वर्कर संगठित कैसे हों यह उसे मालूम नहीं । खान यह भी समझता है कि मामला अकेले कैन्टीन वर्करों के बस का नहीं है, फैक्ट्री और कैन्टीन वर्कर मिलकर ही रास्ता निकाल सकते हैं ।

और यह एक खान या एक बहादुर की ही कहानी नहीं है । यह कैन्टीन के कैजुअल वर्करों का ही किस्सा भी नहीं है । कैजुअल और ठेकेदारों के मजदूरों मात्र का भी यह मामला नहीं है । उन्नीस-बीस के फर्क के साथ यह हर मजदूर की कहानी है आज । पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट में किसी भी मजदूर को अपनी नौकरी पक्की होने का अब भरोसा नहीं है । मैटल बाक्स-ऊषा स्पिनिंग-गेडोर आदि-आदि मजदूरों के सामने हैं मजदूरों की दुख दर्द भरी जिन्दगी को और रसातल में धकेला जा रहा है । ऐसे में दुख दर्द की जननी इस व्यवस्था को समझना और इसे दफनाने के लिये कदम उठाना हर मजदूर का अपने स्वयं के प्रति भी फर्ज है । दमन-शोषण वाली पूंजीवादी व्यवस्था को दफनाने और हंसी-खुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण के लिये आओ मिलकर विचार-विमर्श करें और कदम उठायें ।

—0—

डी. टी. सी. मजदूरों का अनुभव

ट्रान्सपोर्ट वर्कर खराब वर्किंग कन्डीशनों से काफी परेशान रहते हैं—यात्रियों को अक्सर इनके चिड़चिड़ेपन का शिकार होना पड़ता है ।

काफी दिन पहले कांग्रेसियों के आपसी झगड़े में एक सरगने ने जब डी टी सी मजदूरों के गुस्से को भुनाया तब इन मजदूरों की दिल्ली के तन्त्र को अस्त-व्यस्त करने की ताकत का काफी लोगों को अहसास हुआ । कांग्रेस ने इस पर डी टी सी मजदूरों को पुचकार कर अपनी झोली में रखने की कोशिश की । लेकिन पूंजी के नुमाइन्दों और मजदूरों के बीच की अटल शत्रुता शीघ्र ही सामने आ गई । चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने डी टी सी में लागू नहीं की । नये वेतन स्केल की मुख्य मांग के इर्द-गिर्द मजदूरों के असन्तोष को बढ़ते देख कांग्रेसियों ने साजिश रची । एक तरफ कांग्रेसियों ने ही डी टी सी मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाया और दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने ही हड़ताल को कुचलने की तैयारी की । डी टी सी मजदूरों की मारक क्षमता को कम करने और ऊपर से बन्धी-बन्धाई मोटी रिश्वत के वास्ते राजेश पायलेट ने प्राइवेट बसों की बाढ़ लाने की स्कीम बनाई । इन दो कांग्रेसी पाटों में मार्च 1988 में "हड़ताल" के दौरान डी टी सी मजदूरों का कचूमर निकाला ।

कांग्रेस से खार खाये डी टी सी मजदूरों को जनता दल से बहुत उम्मीदें थी । जनतादल नेताओं ने अपने भाषणों में डी टी सी मजदूरों की मांगों का बढ़-चढ़ कर समर्थन किया था । जनता दल की सरकार बनें जब काफी समय हो गया और डी टी सी मजदूरों की वेतन आदि मुख्य मांगों पर कुछ नहीं किया गया तब इन मजदूरों का असन्तोष बढ़ने लगा । इस पर कांग्रेसियों की ही तर्ज पर जनता दल के कुछ लीडरों ने डी टी सी मजदूरों के असन्तोष को भुनाने की कोशिश की । जनता दल की उठा-पटक में अपनी ताकत दिखाने के लिये इन लोगों ने 11 मई को डी टी सी मजदूरों का मोर्चा निकाला । मजदूरों को यह-वह दिलाने के नाम पर इक्कट्ठा किया गया था पर जब मजदूरों को पता चला कि मिलना-जुलना कुछ नहीं तब वे भड़क उठे । जनता दल लीडर अपीलें करते रहे, धमकियाँ भी देते रहे पर मजदूरों ने उनकी एक न सुनी और उठ कर चल दिये । डी टी सी मजदूरों ने कांग्रेस और जनता दल का जुड़वाँ भाई पाया है ।

बिचौलियों पर आस मजदूरों की बरबादी की राह है । सचेत संगठित संघर्ष और बागडोर अपने हाथों में रख कर ही मजदूर आगे बढ़ सकते हैं । डी टी सी मजदूर जान लें कि दक्षिण कोरिया के रेलवे मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में मार्च 1989 में तीन दिन तक 25 लाख यात्रियों को मुफ्त रेल यात्रा करवाई । डी टी सी मजदूरों को अपनी और यात्रियों की सांझी ताकत को मजदूरों-मेहनतकशों के दुश्मन, इस पूंजीवादी तन्त्र के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिये दक्षिण कोरिया के रेलवे मजदूरों से सीखना चाहिये ।

—x—

नकारना जरूरी, समझना और भी जरूरी

रूस में पूंजी

कुछ समय से नित नई शोशेबाजी वाले रूस में मई के आरम्भ से एक नये शोशे को जोर-शोर से हवा दी जा रही है । **मामला बीस लाख मजदूरों की तत्काल छटनी का है ।** इसके लिये आढ़ा टेढ़ा प्रचार जोरों पर है श्रम संसाधन और रोजगार विभाग के डाइरेक्टर वैलेरी कोलोसोव की बातें देखिये :—अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड से इस समय भी रूस में बीस

(शेष अगले पेज पर)

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना । 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना । 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना । 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना ।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत के लिये बेझिझक मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे ।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद—121001

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लाख लोग बेरोजगार हैं। राज्य श्रम समिति का अन्दाजा है कि घाटे में चल रहे जिन कारखानों को बन्द किया जा रहा है उनके होने वाली बड़े पैमाने की छटनी से बीस लाख मजदूर शीघ्र ही बेरोजगारों की कतारों में शामिल हो जायेंगे। पहली बार काम की तलाश में निकलने वाले पन्द्रह लाख नौजवानों में से दस लाख को काम नहीं मिलेगा। 1995 तक रूस में साठ लाख लोग बेरोजगार हो जायेंगे। वैसे बेरोजगारी की असल तस्वीर देखें तो इस समय ही रूस में बैठे मक्खियाँ मारते लगभग एक करोड़ लोग हैं जिनकी छुट्टी करनी है। यह थी श्री कोलोसोव की बातें और आइये अब राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव को सुने :—रूस में जिस काम को तीन लोग करते हैं उसे यूरोप-अमरीका में एक व्यक्ति करता है। रूस में बेरोजगारी का होना अनिवार्य है·····पर·····पर यह टेम्परेरी होगी। और आखिर में प्रधान मन्त्री रिझकोव को भी सुन ही लें :—रूस में सर्विस सैक्टर में एक करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं ···· दिवालिया कारखानों से जिन्हें निकाला जायेगा उन्हें वहां खपाया जा सकता है। वैसे भी कोलोसोव भी दस हजार करोड़ रुपये की बेरोजगार राहत स्कीम का झुनझुना बजाते हैं। **वास्तव में रूस-चीन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में "एकतन्त्र" की जगह "जनतन्त्र" लाने के प्रयासों के पीछे कम मजदूरों से कम तनखा पर ज्यादा काम ले कर विश्व पूंजीवादी होड़ में बने रहने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर छंटनी और बेरोजगारी जैसे मजदूर-विरोधी कदम छिपे हैं।**

रूसी खुफिया पुलिस का चीफ गोर्बाचोव जब से रूसी शासन-तन्त्र का प्रमुख बना है तब से रूस का सरकारी प्रचार-तन्त्र वहाँ अगली पिछली घिनौनी हकीकत के इस-उस पहलू को अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ ज्यादा ही उछाल रहा है। जिस तर्ज पर इन्दिरा गांधी ने बड़े बिस्फोट के खतरे से बचने के लिये छोटे-छोटे धमाके होने देने को इमरजैन्सी हटाने का कारण बताया था उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए गोर्बाचोव भी "एकतन्त्र" की जगह "जनतन्त्र" का जाप कर रहा है। और यह सच है कि खुफिया पुलिस का प्रमुख रह चुका राष्ट्रपति खतरे को सही-सही भाँप रहा है—रूस में तथा पूर्वी यूरोप में हाल ही में जो कुछ हुआ है उसने गोर्बाचोव के ना नुकुर करने वाले उसके संगी-साथियों को भी उसकी बातों का वजन बखूबी दिखा दिया है। वैसे यह बात तो खैर पूंजी के नुमाइन्दों की समझ के दायरे से ही बाहर है कि संकट पूंजी का है, उसके इस या उस रूप का नहीं।

भारत में जनतन्त्र-इमरजैन्सी-जनतन्त्र-आज अराजकता की राह इमरजैन्सी या क्रान्ति की तरफ बढ़ते कदम हों या पाकिस्तान में जनतन्त्र-फौजी शासन-जनतन्त्र····· वाले कदम, शोषण को बनाये रखने व बढ़ाने के लिये जब शासन का एक रूप ज्यादा बदनाम हो जाता है तब नई आड़, नया मेकअप आवश्यक हो जाता है। पिछले सौ साल की दुनियाँ-भर की घटनाओं पर नजर डालने पर शासन-तन्त्रों द्वारा नकाब बदलने की रफ्तार में आई तेजी साफ-साफ दिखाई देती है। आजकल तो यह रफ्तार और भी बढ़ गई है। दरअसल यह पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट से निकलने के लिये पूंजीवादियों की तिनकों के लिये बदहवास चाह का लक्षण मात्र है। रूस में गोर्बाचोव की अगुवाई में शोषण को नई आड़ देने की ऐसी ही कोशिशें और पूंजीवादी संकट के भंवर से निकलने के लिये तिनकों की बदहवास खोज आजकल जोरों पर है।

पिछले साठ—सत्तर साल से दुनियाँ-भर में पूंजीवादी प्रचार दो धुरियों के इर्द-गिर्द संगठित है। एक धुरी विभिन्न किस्म के पूंजीवादी जनतन्त्र रही है और दूसरी धुरी अलग-अलग तरह के पूंजीवादी एकतन्त्र रहे हैं। चालीसेक साल से अमरीकी मोडल वाला पूंजीवादी जनतन्त्र और रूसी मोडल वाला राज्य-पूंजीवादी एकतन्त्र यह दो धुरियाँ बने। रूस-चीन-पूर्वी यूरोप की हाल की घटनाओं ने पूंजीवादी जनतन्त्र के प्रचार को जहाँ सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है वहीं राज्य-पूंजीवादी प्रचार को रसातल में धकेल दिया है। पर यह टेम्परेरी घटना है——गोर्बाचोव ने जो कारण बताया है उसकी वजह से नहीं बल्कि इसलिये कि संकट सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का है, उसके इस-उस रूप या अंग का नहीं। हमारी आँखों के सामने पूंजीवादी जनतन्त्रों में बढ़ता संकट वहाँ एकतन्त्रीय पूंजीवाद की समर्थक शक्तियों को बढ़ा रहा है——पाकिस्तान और भारत में तो इसके उग्र लक्षण सामने आने भी लगे हैं और अगर यह आने वाले दिनों में फैलते अंधड़ का रूप धारण कर ले तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। खैर!

हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि पूंजीवादी जनतन्त्र आज फूल कर कुप्पा हो रहा है और राज्य पूंजीवादी सूख कर कांटा बन रहे हैं। न ही हमारी दिलचस्पी भिन्न—भिन्न रूप-रंग वाले राज्य-पूंजीवादियों के कुतर्कों में है। कोसने दीजिये इन्हें गोर्बाचोव-ख्रुश्चेव—स्तालिन को या गाने दीजिये इन्हें गोर्बाचोव—स्तालिन-ट्राटस्की-लेनिन के गीत। मजदूरों के लिए और क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन के लिए तो उस घटनाक्रम पर नजर डालना तथा उससे सबक लेना जरूरी है जिसके फलस्वरूप राज्य-पूंजीवादी दमन-शोषण को समाजवादी निर्माण करार दे कर दुनियां-भर में मजदूरों को साठ-सत्तर साल तक गुमराह किया गया। भावना से कम्युनिस्ट रहे उन लोगों को जोकि अब छाती पीट रहे हैं, उनसे भी हम तो यही कहेंगे कि दरअसल उन्हें कुछ माथा-पच्ची करनी चाहिये। जगह कम है पर फिर भी आइये दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर पिछली कुछ घटनाएं देखें।

पूंजीवादी व्यवस्था की पतनशील अवस्था के पहले बड़े संकट ने 1914 में दुनियाँ के पैमाने पर लुटेरों के बीच मार-काट को जन्म दिया। पांच साल चले उस पूंजीवादी कत्ले-आम में ढाई करोड़ लोग मारे गये थे। उस खून-खराबे के खिलाफ 1917 में मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी लहर उठी। रूस-जर्मनी-आस्ट्रीया-हंगेरी-इटली-इंग्लैंड आदि में जोर पकड़ती वह मजदूर लहर रूस में इतनी ऊंचाई तक उठी कि हथियारबन्द मजदूरों ने वहाँ पुलिस-फौज को भग करके पूंजीवादी राज्य-तन्त्र को तहस-नहस कर दिया। आम मजदूर हथियारों से लैस थे और अक्तूबर 1917 में वर्कर्स सोवियतों/मजदूर परिषदों के रूप में रूस में मजदूर वर्ग की तानाशाही कायम हुई। सठियाते जाने के साथ दुख-दर्द को बेहद बढ़ाती जा रही दमन-शोषण वाली पूंजीवादी व्यवस्था को दफनाने की राह में यह एक महान कदम था। समाजवाद के रास्ते हंसी-खुशी भरे खुशहाल साम्यवादी समाज की तरफ यह एक मजबूत कदम था।

पर जर्मनी-आस्ट्रीया-हंगेरी में क्रान्तिकारी मजदूरों को पूंजीवादी शक्तियों ने हरा दिया। इटली आदि में पूंजीवादी राज्य-तन्त्र के पुलिस—फौज जैसे स्तम्भों को ढहाये बगैर फैक्ट्रियों पर कब्जे के चक्करों आदि में मजदूर उलझ गए। पूंजीवाद के खिलाफ उठी उस क्रान्तिकारी मजदूर लहर में उतार आने लगा। और इसके साथ ही रूस में क्रान्तिकारियों के गर्भ से ही प्रतिक्रान्ति उभरी। रूस में क्रान्ति के अगुवा दस्ते, बोल्शेविक पार्टी ने 1918 में ही नये सिरे से फौज बनाने जैसे उल्टे कदम उठाने शुरू कर दिए थे। क्रान्तिकारी लहर के कमजोर पड़ते जाने के साथ—साथ रूस में बोल्शेविकों ने पुलिस-फौज के तन्त्र को मजबूत करना शुरू किया और मजदूरों से हथियार रखवाने लगे। शीघ्र ही रूस में भी मजदूर निहत्थे कर दिए गये और मजदूरों के अपने भले के नाम पर मजदूरों को हांका जाने लगा। मजदूरों ने विरोध किया पर मजदूरों की हड़तालों को 1921 से ही बोल्शेविक पार्टी ने पुलिस-फौज की मदद से तोड़ना शुरू कर दिया था।

आरम्भ में बोल्शेविक पार्टी ने रूस में राज्य-पूंजीवाद को समाजवाद की तरफ बढ़ने के लिए एक "जरूरी बुराई" के तौर पर लिया। बोल्शेविक पार्टी के मुताबिक मजदूर इसे नहीं समझते थे। इसीलिए रूस में मजदूरों द्वारा राज्य-पूंजीवाद के विरोध को शुरू—शुरू में बोल्शेविक पार्टी ने "मजदूरों के अपने भले" के लिये पुलिस-फौज तक का इस्तेमाल करके कुचला। पर जल्दी ही रूस में राज्य-पूंजीवाद नंगा नाचने लगा। पूंजी की तीव्र बढ़ोतरी के लिये रूस में ताँडव शुरू हुआ——नरमुन्डों की माला स्तालिन के गले में पड़ी। मजदूरों के प्रति क्रूर दमन-शोषण के लिए विभिन्न हथकन्डे इस्तेमाल किये गये और लम्बे समय तक राज्य-पूंजीवादियों ने हर कुकृत्य को "समाजवाद के निर्माण के लिये आवश्यक" करार दे कर जायज ठहराया।

नाम बेशक लाल फौज था पर 1918 में ही इसके गठन के दौरान वह कदम उठाये गये कि वह असल फौज बन गई। फौज और मजदूर राज साथ-साथ नहीं चल सकते। इसलिए रूस में 1918 से ही तेजी से बढ़ते पुलिस-फौज तन्त्र के साथ मजदूरों का शासन शीघ्र ही खत्म हो गया। रूस में इन साठ-सत्तर साल से पूंजी के राज्य-पूंजीवादी रूप का राज रहा है। पूंजवादी कुप्रचार दमनकारी विशाल पुलिस-फौज वाले राज्य-पूंजीवादी तन्त्र को समाजवाद कह कर समाजवाद को बदनाम करता रहा है। रूस और उस जैसे देशों को कम्युनिष्ट देश कह कर पूंजीवादी कुप्रचार क्रूर दमन-शोषण को मजदूरों के स्वर्ग करार दे कर मजदूरों के मुक्ति संघर्षों को दलदल में फसाने की कोशिशों में लगा रहा है।

वास्तव में पूंजी एक सामाजिक सम्बन्ध है। मजदूर लगा कर मंडी के लिए प्रोडक्शन पूंजी का सार है। पूंजी वाला सामाजिक सम्बन्ध दुनियाँ के पैमाने पर काम करता है, इसे एक देश के दायरे में खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के दौर के बिस्फोट जब क्रान्तिकारी रूप धारण कर लेते हैं तब उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वे विकल्प में विश्व साम्यवादी व्यवस्था उभारें। पर समाज की जटिलता के कारण पूंजीवाद विरोधी क्रान्तिकारी प्रक्रिया का रास्ता सीधा-सपाट नहीं है। विरासत में मिली बेड़ियाँ एक झटके में नहीं टूटेंगी। क्रान्तिकारी प्रक्रिया लहरों का एक सिलसिला है जिन्हें उस ऊंचाई तक उठना होगा कि वह पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को दफना दें। और जब तक पूंजीवाद है, इसका गहराता संकट एक से बढ़कर एक क्रान्तिकारी लहर के उठने के लिये परिस्थितियाँ पैदा करेगा——बशर्ते पूंजीवादी व्यवस्था का गहराता संकट सम्पूर्ण मानव जाति को ही न ले डूबे। इसलिए रूस की घटनाओं से हमें एक सबक तो यह लेना चाहिए कि एक क्रान्तिकारी लहर द्वारा मंजिल फतह न कर पाने पर बदहवासी में फौज बनाने जैसे कदम उठा कर भविष्य की क्रान्तिकारी सम्भावनाओं की राह में रोड़े नहीं डालें।

—x—

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अलकनन्दा प्रिंटिंग प्रेस C-III/206, सं. गां. मेमो. न. से मुद्रित